



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 68/18

निर्णय दिनांक:-19.06.2018

1. जीत सिंह पुत्र दिलीप सिंह जाति रामगड़िया निवासी चक 2 सीसी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोंडेन्ट्

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 30-01-1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़, मु. बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री धनेश खत्री, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट् ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेरके आदेश दिनांक 30-01-1999 जिसके द्वारा अपीलांट् का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना निलामी में उपस्थित नहीं होने के कारण खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् द्वारा तहसील पूगल में चक 18 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 33/52 में 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र

प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि हेतु अन्य आवेदक मुसे खॉ ने भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था अपीलांट व मूसे खॉ की समान वरियता होने के कारण नीलामी के द्वारा मूसे को वादगत् भूमि आवंटित हो चुकी है। अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30-01-1999 के विरुद्ध अपील दिनांक 19-01-18 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र उपस्थित नहीं आने के कारण व वादगत् भूमि अन्य को आवंटित की जा चुकी है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. (1) जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 30-01-1999 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 19-01-2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांत ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए तहसील पूगल के चक 18 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 33/52 में 25 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई थी।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांत का आवेदन पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी को आवेदित रकबे के आवंटन हेतु जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आया। आवेदित रकबे हेतु अन्य प्रार्थी मूसे खॉ के उपस्थित आने पर मूसे खॉ द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की राय से 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई जाकर भूमि आवंटन की जा चुकी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति की राय से खारिज किया जाता है।

(4) इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांत को वादगत् भूमि के आवंटन हेतु जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब की किया। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांत के अतिरिक्त अन्य आवेदक मूसे खॉ द्वारा आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा था। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांत को जयिये रजिस्टर्ड नोटिस

द्वारा तलब किये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं आने पर वादगत् भूमि अन्य आवेदक मूसे खॉ को आवंटन किया जा चुका हैं। विशेष आवंटन के नियमों में आवेदक द्वारा आवेदित भूमि के आवंटन का ही प्रावधान निहित है अन्यत्र भूमि के आवंटन का प्रावधान नहीं है।

(5) जब अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा अन्य आवेदित प्रार्थी को आवंटित हो चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट/प्रार्थी द्वारा आवेदित रकबा अब अपीलांट को आवंटन नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र आवेदित रकबा अन्य को आवंटित होने क आधार पर खारिज करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जो विधि सम्मत है तथा खारिज की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत का आदेश दिनांक 30-01-1999 बहाल रखा जाता है।
8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 19.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर